नईदुनिया

संपादकीय

भरोसा जब कुर्सी से उतरकर जमीन पर आए

जागृति *अवस्थी ने दिखाया कि आईएएस भी सरकारी अस्पताल पर भरोसा कर सकता है। सोनभद्र के एमसीएच विंग में बेटे का जन्म एक बड़ा संदेश है। यदि सभी नेता और अधिकारी ऐसा करें तो व्यवस्था खुद सुधर जाएगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक महिला आईएएस अधिकारी जागृति अवस्थी ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति भरोसे का बड़ा संदेश दिया है। जिले की मुख्य विकास अधिकारी और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 की सेकंड टॉपर जागृति अवस्थी ने अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए सोनभद्र के सरकारी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग को चुना। यहां उन्होंने बेटे को जन्म दिया। उनके पति गौरव पांडेय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और मध्यप्रदेश में तैनात हैं। एक आईएएस-आईपीएस परिवार चाहता तो देश के किसी महंगे निजी अस्पताल में प्रसव करा सकता था, लेकिन उन्होंने सरकारी अस्पताल को चुना।*

यह केवल एक प्रसव नहीं, बल्कि एक विचार, साहस और उदाहरण है। हमारे देश में एक अजीब परंपरा बन गई है। जो सरकारी व्यवस्था चलाता है, वही उस पर भरोसा नहीं करता। नेता के बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं। अधिकारियों का इलाज निजी अस्पतालों में होता है, सरकारी अस्पतालों में नहीं। मंत्रियों के परिवार विदेश में इलाज कराते हैं। फिर सवाल उठता है कि जब व्यवस्था चलाने वालों को ही अपनी बनाई व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो आम आदमी कैसे भरोसा करे? आम आदमी के पास तो विकल्प भी नहीं है। वह मजबूरी में सरकारी स्कूल और अस्पताल जाता है और वहीं उसे बदहाल व्यवस्था का अनुभव होता है। जागृति अवस्थी ने इस परंपरा को तोड़ा है। उन्होंने सरकारी अस्पताल को चुना तो जाहिर है कि उन्हें वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भरोसा था। एक अधिकारी जब अपने जिले के अस्पताल में भर्ती होती है तो पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाता है, लेकिन यहां बात केवल अलर्ट होने की नहीं, बल्कि भरोसे की है। यह भरोसा तभी पैदा होता है, जब व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास जमीन पर दिखाई देते हैं। सोचिए, यदि देश के सभी नेता, आईएएस और आईपीएस अधिकारी सरकारी स्कूलों और अस्पतालों पर भरोसा करने लगें तो क्या होगा? यदि हर सांसद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे तो क्या वहां अव्यवस्था बनी रहेगी? क्या शिक्षक गैरहाजिर रहेंगे और शौचालय गंदे रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि जिस दिन बड़े अधिकारियों और नेताओं के बच्चे उसी व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, उसी दिन उसकी गुणवत्ता सुधारने का दबाव भी बढ़ेगा। व्यवस्था इसलिए खराब है क्योंकि उसका उपयोग करने वाले आमतौर पर कमजोर और गरीब हैं और उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। यही बात अस्पतालों पर भी लागू होती है।

यदि विधायक, मंत्री और अधिकारी उसी जिला अस्पताल में इलाज कराएं, जहां आम आदमी जाता है, तो डॉक्टरों की अनुपस्थिति, खराब मशीनों और दलाली जैसी समस्याओं पर स्वत: अंकुश लगाने का दबाव बनेगा। यह फॉर्मूला सरल है, लेकिन लागू करना कठिन है, क्योंकि हमारे देश के बड़े लोग सुविधाओं से ज्यादा स्टेटस को महत्व देते हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज कराना उन्हें अपनी हैसियत के खिलाफ लगता है। जागृति अवस्थी का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्भावस्था और प्रसव को लेकर समाज में अनेक आशंकाएं हैं। अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि सरकारी अस्पतालों में खतरा है और निजी अस्पतालों में ही सुरक्षा है। इसी डर के नाम पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। एक आईएएस अधिकारी ने सरकारी एमसीएच विंग पर भरोसा जताकर उन महिलाओं को भी हिम्मत दी है, जो आर्थिक मजबूरी के कारण निजी अस्पतालों में नहीं जा सकतीं। जागृति अवस्थी और उनके पति गौरव पांडेय को इस निर्णय के लिए सलाम। देश को भाषण नहीं, ऐसे उदाहरण चाहिए, जो बताएं कि सरकारी व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। अधिकारियों और नेताओं को भी अपने जिले के स्कूलों और अस्पतालों पर भरोसा करना चाहिए। उनका भरोसा ही करोड़ों लोगों का भरोसा बन सकता है।

आजकल

छत का सपना अधूरा, झुग्गियों का दायरा पूरा

आठ साल में सिर्फ नौ लाख मकान, बीस लाख की जरूरत कैसे होगी पूरी

मध्यप्रदेश में शहरों को झुग्गी बस्तियों से मुक्त करने और गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराने की चुनौती लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में अभी करीब 17 लाख 17 हजार किफायती आवासों की कमी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2018 से 2026 के बीच महज नौ लाख मकान ही बन पाए हैं। सबसे बड़ी बाधा शहरों में जमीन की उपलब्धता है। इसके चलते योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। नतीजतन, झुग्गी बस्तियों का विस्तार हो रहा है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण भी बढ़ रहा है। यह आंकड़ा केवल मकानों की कमी नहीं, बल्कि शहरों के बिखरते स्वरूप की कहानी भी बयां करता है।

नगरीय विकास विभाग के आकलन के अनुसार, वर्ष 2036 तक प्रदेश में कुल 20 लाख 82 हजार 199 आवासों की जरूरत होगी। इनमें 17 लाख 17 हजार 393 किफायती आवास शामिल हैं। यानी कुल आवासीय मांग का बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों से जुड़ा है। इसके बाद 2037 से 2047 के बीच 18 लाख 46 हजार 889 अतिरिक्त आवासों की जरूरत का अनुमान है। स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में आवास की मांग और बढ़ेगी।

आठ साल में महज नौ लाख मकान बनने की वजह जमीन की कमी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग जैसे घटकों के जरिए निजी भागीदारी से भी मकान बनाने की व्यवस्था है, लेकिन इन दोनों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। इसकी बड़ी वजह जमीन की अनुपलब्धता और निजी निवेशकों की सीमित भागीदारी है। सरकार अब अलग लैंड बैंक बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि गरीबों और निम्न आय वर्ग के लिए जमीन सुरक्षित रखी जा सके। नई नीति में निजी निवेश बढ़ाने के लिए तीन मॉडल प्रस्तावित हैं। पहले मॉडल में सरकारी जमीन पर पीपीपी, जॉइंट वेंचर या दीर्घकालिक लीज के जरिए निजी डेवलपर्स मकान बनाएंगे। दूसरे में निजी जमीन पर मिश्रित आय वर्ग की परियोजनाएं विकसित होंगी। तीसरे मॉडल में सरकारी जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा, जबकि निर्माण निजी निवेशक करेंगे। तीनों मॉडलों में स्वीकृत एफएआर का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासों के लिए रखना होगा। हालांकि, केवल मकान बनाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें शहरों के भीतर परिवहन, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना भी जरूरी है। गरीब को शहर से 20 किलोमीटर दूर मकान दे देने से समस्या हल नहीं होगी। वह वहीं रहना पसंद करेगा, जहां उसे रोजगार मिलता है। इसलिए लैंड बैंक शहर के भीतर होना चाहिए, बाहरी इलाकों में नहीं।

झुग्गियों का बढ़ता दायरा सरकार के लिए चेतावनी है। जब लाखों परिवारों के पास पक्की छत नहीं होगी, तो वे सरकारी जमीन पर ही बसेंगे। इससे अतिक्रमण, गंदगी और अव्यवस्था बढ़ेगी। बाद में जमीन खाली कराने पर सरकार को कई गुना अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसलिए अभी निवेश करना अधिक किफायती है। वर्ष 2036 तक 20 लाख से अधिक आवासों की जरूरत है, जबकि आठ साल में केवल नौ लाख मकान बने हैं। निर्माण की गति लगभग तीन गुना करनी होगी, अन्यथा झुग्गियां ही भविष्य के शहरों की पहचान बन जाएंगी।

आकाश में बदला युद्ध का चेहरा, अब विमान नहीं एल्गोरिदम लड़ेंगे



ड्रोन स्वार्म से लेकर कामिकेज हमलों तक वायुसेना की नई प्रयोगशालाएं। गैर-संपर्क युद्ध की तैयारी, जहां सैनिक नहीं, मिसाइलें और सिग्नल लड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और अंतरिक्ष तीन नए मोर्चे, जहां भविष्य की जीत तय होगी। चौंकाने की क्षमता ही नया ब्रह्मास्त्र है। दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा।

युद्ध अब वह नहीं रहा, जो बीस साल पहले हुआ करता था। पहले युद्ध में टैंक चलते थे, तोपें गरजती थीं और पैदल सेना आगे बढ़ती थी। अब युद्ध में सबसे पहले सिग्नल चलता है, नेटवर्क टूटता है और रडार अंधा होता है। आधुनिक युद्ध पारंपरिक युद्धक्षेत्रों से आगे बढ़कर गैर-संपर्क वाले क्षेत्रों तक फैल गया है, जहां मिसाइलें, ड्रोन और उन्नत हथियार प्रणालियां अहम भूमिका निभा रही हैं। रूस-यूक्रेन के युद्धक्षेत्र में यह साफ दिखाई दिया है और इजरायल-हमास संघर्ष ने इसे और पुख्ता किया है। ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियां आधुनिक युद्ध के अहम घटक बनकर उभरी हैं। इसी बदलाव ने भारतीय वायुसेना को भी नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है।

वायुसेना में इस समय सबसे बड़ा नवाचार स्वार्म ड्रोन का है। एक-दो नहीं, बल्कि सौ-दो सौ छोटे ड्रोन एक साथ उड़ते हैं और दुश्मन के रडार को भ्रमित कर देते हैं। किसी एक को मार गिराओ तो दूसरा हमला कर देता है। यह झुंड आत्मघाती भी हो सकता है, जिसे कामिकेज ड्रोन कहा जाता है। ये सीधे जाकर दुश्मन के बंकर या रडार से टकरा जाते हैं। इनकी लागत एक मिसाइल की तुलना में सौ गुना तक कम हो सकती है और इनका असर उतना ही घातक हो सकता है। भारतीय प्रयोगशालाओं में अब स्वदेशी स्वार्म ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं, जो बिना जीपीएस के भी दुश्मन के इलाके में नेविगेट कर सकते हैं और वापस लौट सकते हैं। ड्रोन रोधी प्रणालियां भी उतनी ही जरूरी हैं। जिस तरह ड्रोन हमला करना सीख रहे हैं, उसी तरह उन्हें रोकने की क्षमता विकसित करना भी आवश्यक है। वायुसेना अब ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है, जो आकाश में ही ड्रोन को पकड़ सके। इसमें लेजर हथियार हैं, जो ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। जैमर हैं, जो ड्रोन का सिग्नल तोड़ देते हैं और काइनेटिक सिस्टम हैं, जो छोटे रॉकेट से ड्रोन को मार गिराते हैं। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आने वाले हथियारबंद ड्रोन को रोकने के लिए यह प्रणाली बेहद जरूरी है और इसके परीक्षण भी तेजी से चल रहे हैं।

भविष्य के युद्ध में जो रडार को पहले अंधा करेगा, वही बढ़त हासिल करेगा। भारतीय वायुसेना अब अपने सुखोई और राफेल विमानों पर स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगाने की दिशा में काम कर रही है, जो दुश्मन की मिसाइलों को रास्ते से भटका सकते हैं। साथ ही ऐसी प्रणालियां विकसित की जा रही हैं, जो दुश्मन के संचार को सुन सकें और उसे गलत संदेश भेज सकें। इसे स्पूफिंग कहा जाता है। युद्ध में यदि दुश्मन को लगे कि उसके विमान उत्तर में हैं, जबकि वे दक्षिण में हैं, तो उसकी पूरी रणनीति प्रभावित हो सकती है। साइबर और अंतरिक्ष भी युद्ध के नए मोर्चे बन चुके हैं। आज हर हथियार नेटवर्क से जुड़ा है। यदि नेटवर्क हैक हो गया तो हथियार बेकार हो सकते हैं। इसलिए वायुसेना साइबर कमान को मजबूत कर रही है। ऐसी टीमें तैयार की जा रही हैं, जो युद्ध के समय दुश्मन के एयरबेस के कंप्यूटर नेटवर्क को बाधित कर सकें और उसके विमानों के संचालन को प्रभावित कर सकें। अंतरिक्ष में भी यही स्थिति है। उपग्रहों से निगरानी होती है। यदि युद्ध के दौरान उपग्रह निष्क्रिय हो गया तो हमारी निगरानी और संचार क्षमताएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक विकसित किया है और ऐसे उपग्रह तैयार करने की दिशा में भी काम कर रहा है, जो जरूरत पड़ने पर दूसरे उपग्रहों की जगह ले सकें। पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों तरह की कार्रवाई में दुश्मन को चौंकाना ही जीत की अहम रणनीति है। चौंकाने वाली कार्रवाई का मतलब ऐसी क्षमता विकसित करना है, जिससे शत्रु को प्रतिक्रिया देने या संभलने का मौका ही न मिले। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि दुश्मन की किसी अप्रत्याशित चाल से हम स्वयं हैरान न हों। इसके लिए खुफिया और निगरानी क्षमताओं को लगातार मजबूत करना, विभिन्न प्रणालियों के बीच तालमेल बढ़ाना और संभावित खतरों को सामने आने से पहले पहचानना जरूरी है। भविष्य के युद्ध में जीत केवल विमानों की संख्या पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि उन्नत तकनीक, जवाब देने की गति और तैयारियों की सटीकता पर भी निर्भर करेगी।

वायुसेना अब इस दिशा में अपनी संस्थागत सोच बदल रही है। अब हर योजना में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक, दोनों पहलुओं को शामिल किया जा रहा है। युद्ध के उभरते क्षेत्रों के लिए विशेष सिद्धांत और ढांचे विकसित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए अलग मैनुअल, साइबर युद्ध के लिए अलग प्रोटोकॉल और अंतरिक्ष युद्ध के लिए अलग रणनीति तैयार की जा रही है। इससे तीनों सेनाओं के बीच तालमेल भी बढ़ेगा, क्योंकि आने वाला युद्ध अकेले वायुसेना नहीं लड़ेगी। सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ एक थिएटर में युद्ध लड़ेंगी और इसी एकीकरण की तैयारी चल रही है। यह सब नवाचार क्यों जरूरी है? भारत के सामने दो चुनौतियां हैं। पहली, सीमा पर घुसपैठ और ड्रोन का खतरा। दूसरी, सीमा के पार तकनीकी प्रतिस्पर्धा। चीन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारी निवेश किया है और पाकिस्तान सस्ते ड्रोन के जरिये हमें उलझाना चाहता है। इसलिए हमें सस्ता और स्मार्ट, दोनों बनना होगा। सस्ते ड्रोन, स्मार्ट जैमर और स्वदेशी उपग्रह, यही भविष्य का त्रिकोण है। जो देश इस त्रिकोण को पहले विकसित कर लेगा, वही आकाश पर राज करेगा और जो आकाश पर राज करेगा, वही भविष्य के युद्ध में दुश्मन को चौंकाएगा और जीत हासिल करेगा। **(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)**

मध्यप्रदेश की किस्मत बदलेगा पानी से बिजली का बैंक



गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज जून 2027 से देगा पूरी क्षमता से बिजली। 11,500 करोड़ की परियोजना से 1,920 मेगावाट बिजली उत्पादन, रोशन होगा प्रदेश। देश का पहला बड़ा प्रोजेक्ट, 414 हेक्टेयर में दो जलाशयों का संगम। ग्रीनको का ग्रीन सपना, बर्बाद होने वाली सौर और पवन ऊर्जा को बचाएगा यह बैंक।

मध्यप्रदेश में ऊर्जा की कहानी अब नया मोड़ लेने जा रही है। डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक की अगली कड़ी में प्रदेश की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में होगी। इस कैबिनेट बैठक की तैयारियां लगातार चल रही हैं। इस दौरान 1,920 मेगावाट क्षमता वाली गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना आकर्षण का केंद्र रहेगी। 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली यह मेगा परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसकी खासियत यह है कि यह न केवल बिजली की कमी को दूर करने में मदद करेगी, बल्कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको कर रहा है। यह देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। 1,920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के एक गांव में स्थापित की जा रही है। करीब 414 हेक्टेयर भूमि पर आकार ले रही इस विशाल परियोजना में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें निचला जलाशय पहले से मौजूद गांधीसागर जलाशय है, जबकि ग्रीनको ने एक नया ऊपरी जलाशय भी बनाया है। इस परियोजना में टरबाइन मोड के जरिए लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड लगभग 122 मीटर है। परियोजना की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को दोबारा बिजली में बदलने की क्षमता लगभग 80 फीसदी रहने का अनुमान है। इसमें कुल नौ टरबाइन लगाए जा रहे हैं। इनसे कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट होगी। अब समझिए कि यह परियोजना आखिर है क्या? आम भाषा में इसे पानी की बैटरी कहा जा सकता है। दिन में जब सौर ऊर्जा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और हवा से भी पर्याप्त बिजली बनती है, तब कई बार ग्रिड को उतनी बिजली की जरूरत नहीं होती। ऐसे में अतिरिक्त बिजली का उपयोग नहीं हो पाता। इस परियोजना में उसी अतिरिक्त बिजली से पानी को निचले जलाशय से पंप करके ऊपर वाले नए जलाशय में पहुंचाया जाएगा। फिर शाम को, जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लोग घर लौटते हैं, एसी चलते हैं और कारखानों में उत्पादन होता है, तब ऊपर वाले जलाशय से पानी नीचे गिराकर टरबाइन के जरिये फिर बिजली बनाई जाएगी। यह प्रक्रिया बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करने जैसी है, लेकिन यह लिथियम बैटरी से कहीं बड़े पैमाने पर ऊर्जा संग्रहित कर सकती है और इसकी उपयोगी उम्र लगभग 50 साल तक हो सकती है। इस परियोजना की एक और खासियत यह है कि यह अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहित करती है। इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा बर्बाद होने से बच जाती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिजली ग्रिड को अधिक लचीला बनाया जा सके, मांग के अनुसार समय पर हरित ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके और देश के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य को गति मिल सके। चंबल नदी पर स्थित गांधीसागर जलाशय एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शामिल है। यह मंदसौर और नीमच जिलों सहित पूरे प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सशक्त केंद्र बन चुका है। मध्यप्रदेश के लिए यह परियोजना गेम चेंजर क्यों है? इसका पहला कारण है बिजली की उपलब्धता में स्थिरता। प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा दिन में ही उपलब्ध होती है, रात में नहीं। पवन ऊर्जा भी मौसम पर निर्भर है। ऐसे में बिजली ग्रिड को एक ऐसी बैटरी की जरूरत है, जो रात में भी हरित बिजली उपलब्ध करा सके। गांधीसागर परियोजना यही भूमिका निभाएगी। दूसरा कारण है रोजगार। 11,500 करोड़ रुपये का निवेश केवल टरबाइन नहीं लाएगा, बल्कि सड़कें, होटल और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। मंदसौर और नीमच जैसे जिलों में यह परियोजना औद्योगिक विकास को गति दे सकती है। तीसरा कारण है पानी का बेहतर उपयोग। गांधीसागर बांध पहले से मौजूद है। नया जलाशय बनने से पानी के भंडारण और ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकेगा।

80 फीसदी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि आप 100 यूनिट बिजली खर्च करके पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो उसमें से लगभग 80 यूनिट बिजली वापस मिल जाएगी। यानी 20 यूनिट ऊर्जा का नुकसान होगा। लेकिन यह नुकसान उस अतिरिक्त बिजली के उपयोग के मुकाबले महत्वपूर्ण नहीं है, जिसका अन्यथा इस्तेमाल नहीं हो पाता। अतिरिक्त बिजली से 80 यूनिट वापस हासिल करना ही इस परियोजना की बड़ी उपलब्धि होगी। दुनिया में पंप्ड हाइड्रो को ऊर्जा भंडारण के सबसे टिकाऊ विकल्पों में से एक माना जाता है। लिथियम बैटरी की तुलना में यह बड़े पैमाने पर लंबे समय तक ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। यह परियोजना छह घंटे तक लगातार 1,920 मेगावाट की क्षमता से बिजली उपलब्ध करा सकेगी। सालाना 3,580 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के साथ यह मध्यप्रदेश के लाखों घरों को हरित बिजली उपलब्ध कराने में मददगार होगी। डेस्टिनेशन कैबिनेट का संदेश भी साफ है। सरकार केवल भोपाल में बैठकर फैसले नहीं लेना चाहती, बल्कि मौके पर जाकर परियोजनाओं की प्रगति देखना चाहती है। गांधीसागर में कैबिनेट बैठक करना इस बात का प्रतीक है कि सरकार इस परियोजना को प्रदेश की सूरत बदलने वाली परियोजना मानती है। जून 2027 से जब यह पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगी, तब मध्यप्रदेश केवल बिजली बनाने वाला राज्य नहीं, बल्कि बिजली का भंडारण करने और जरूरत के समय उसका इस्तेमाल करने वाला राज्य भी बन जाएगा। यह हरित ऊर्जा पर सरकार के फोकस का बड़ा उदाहरण होगा और देश के अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकता है। **(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)**

दुनिया की कंपनियों पर भारतीयों का राज, 236 दिग्गजों की बादशाहत



हुरुन रिपोर्ट में खुलासा, गूगल-माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, भारतीय दिमाग चला रहे 1,250 लाख करोड़ रुपये का साम्राज्य। भारतीय मूल के सीईओ का डंका। सुंदर पिचाई से सत्य नडेला तक, ट्रिलियन क्लब में भारतीयों की धाक। वैश्विक कॉर्पोरेट जगत में भारतीय प्रतिभा और नेतृत्व का परचम और मजबूत हुआ है। हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2026 में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों का नेतृत्व करने वाले 236 भारतीय हैं, जिनके नेतृत्व वाली कंपनियों का कुल मूल्यांकन 1,250 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह आंकड़ा 2024 के पहले संस्करण में दर्ज 9.9 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले 53 फीसदी अधिक है। 2024 की सूची में बाजार मूल्यांकन में 98 फीसदी की भारी उछाल आया, जिसने कंपनी को 4.2 ट्रिलियन डॉलर के मुकाम पर पहुंचा दिया। दूसरी ओर, सत्य नडेला और गूगल क्लाउड के थॉमस कुरियन जैसे भारतीय मूल के दिग्गज भी शीर्ष पर बने हुए हैं।

यह रिपोर्ट केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारत की प्रतिभा की वैश्विक जीत है। 4.2 ट्रिलियन डॉलर के विशाल मूल्यांकन के साथ अल्फाबेट ने माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया में किसी ग्लोबल इंडियन के नेतृत्व वाली सबसे मूल्यवान कंपनी का तमगा हासिल किया है। अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जिन्होंने कंपनी को एआई के युग में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का नेतृत्व सत्य नडेला के हाथों में है, जिन्होंने कंपनी को क्लाउड और एआई की दुनिया में बादशाह बना दिया है। ये दोनों कंपनियां अमेरिकी हैं, लेकिन इनका दिमाग भारतीय है।

हुरुन की इस सूची में सबसे तेज उछाल दर्ज करने वाली कंपनियों का जिक्र भी है। इनमें सबसे तेज 1,174 फीसदी की वृद्धि हुई और यह मूल्यांकन 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यूट्यूब के नील मोहन चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। शीर्ष पांच कंपनियों का कुल मूल्य 9.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो पूरी सूची के कुल मूल्यांकन का लगभग 61 फीसदी है। इसका मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब भारतीय मूल के लोगों के फैसलों पर टिका है। भारतीय ही दुनिया पर क्यों राज कर रहे हैं? इसका जवाब है जुगाड़ नहीं, बल्कि सोच। भारत में शिक्षा, परिवार और संघर्ष, तीनों मिलकर एक ऐसा इंसान तैयार करते हैं, जो कम संसाधनों में ज्यादा करना जानता है। अमेरिकी कंपनियों को अब केवल कोडर नहीं, लीडर चाहिए और नेतृत्व के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं। भारतीय विनम्र भी हैं और कठोर भी। वे टीम को साथ लेकर चलते हैं और तकनीक को समझते हैं। यही वजह है कि गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक और एडोबी से लेकर आईबीएम तक, हर जगह भारतीय मूल के सीईओ नजर आते हैं। इसका भारत को क्या फायदा है? फायदा सीधा है। जब भारतीय मूल के लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मुखिया होंगे तो भारत में निवेश बढ़ेगा, रिसर्च सेंटर खुलेंगे और देश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। पहले इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता था, यानी भारतीय प्रतिभाएं विदेश जा रही हैं। अब ब्रेन गेन की स्थिति बन रही है। यही लोग भारत में निवेश कर रहे हैं, भारतीय स्टार्टअप को खरीद रहे हैं और देश को एआई का हब बनाने में योगदान दे रहे हैं। 1,250 लाख करोड़ रुपये का यह साम्राज्य केवल विदेशी नहीं है, बल्कि भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का साम्राज्य भी है।

दुनिया की कंपनियां भारतीयों को इसलिए नहीं चुन रही हैं कि वे भारतीय हैं, बल्कि इसलिए चुन रही हैं क्योंकि वे काबिल हैं। यदि भारत को सच में विश्वगुरु बनना है तो हमें अपने देश में भी ऐसी ही कंपनियां बनानी होंगी और ऐसे विश्वविद्यालय विकसित करने होंगे, जो सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे नेतृत्वकर्ता तैयार कर सकें। हुरुन की यह सूची हमें बताती है कि भारतीय दिमाग दुनिया पर राज कर सकता है, बस उसे सही मौका और सही माहौल चाहिए।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

84 महादेव दर्शन यात्रा

84 महादेव : श्री रेवन्तेश्वर महादेव (56) : अश्विनी कुमारों की शिव आराधना से जुड़े है उज्जैन के श्री रेवन्तेश्वर महादेव

सूर्यपुत्र रेवन्त का अद्भुत पराक्रम, तीनों लोकों में गूंजा तेज

डॉ. नवीन आनंद जोशी

भारत की प्राचीन धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा में उज्जैन का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। मध्यप्रदेश की यह पावन नगरी भगवान महाकालेश्वर की नगरी के रूप में विश्वविख्यात है। यहां स्थित महाकाल वन का धार्मिक महत्व भी अत्यंत प्राचीन माना गया है। इसी महाकाल वन में विराजमान चौरासी महादेव की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए विशेष पुण्यदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि चौरासी महादेव के दर्शन एवं पूजन से मनुष्य को आध्यात्मिक शांति, आत्मिक शुद्धि और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी पवित्र परंपरा में 56वें स्थान पर पूजित हैं श्री रेवन्तेश्वर महादेव। इनका पौराणिक संबंध भगवान सूर्यदेव, माता संज्ञा, अश्विनी कुमारों और सूर्यपुत्र रेवन्त के दिव्य प्रसंग से जुड़ा हुआ है। यह कथा तेज, तपस्या, पराक्रम, भक्ति और ईश्वरीय कृपा का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है।

सूर्यदेव, माता संज्ञा और दिव्य अश्व का प्रसंग

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान सूर्यदेव का तेज अत्यंत प्रचंड और असहनीय था। उनकी पत्नी माता संज्ञा सूर्यदेव के इस दिव्य तेज को सहन करने में कठिनाई अनुभव करने लगीं। अंतत: उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया और अपने स्थान पर अपनी छाया को छोड़कर स्वयं तप के लिए चली गईं। कुछ समय बाद जब सूर्यदेव को इस बात का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने माता संज्ञा की खोज आरंभ की। खोजते-खोजते वे कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां माता संज्ञा अश्व अर्थात घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन थीं। सूर्यदेव ने भी अश्व का रूप धारण किया और माता संज्ञा के समीप पहुंचे। इस दिव्य संयोग से अश्विनी कुमारों का प्राकट्य हुआ। अश्विनी कुमार अपनी असाधारण दिव्य शक्तियों, ज्ञान और चिकित्सा कौशल के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्हें देवताओं का वैद्य माना जाता है। पौराणिक परंपरा में इसी सूर्यवंशीय प्रसंग से रेवन्त के प्राकट्य का भी उल्लेख मिलता है। रेवन्त को अत्यंत तेजस्वी, साहसी और पराक्रमी माना गया है। वे शस्त्रविद्या में निपुण थे तथा खड्ग धारण करने वाले दिव्य योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनका व्यक्तित्व साहस, शक्ति और अदम्य पराक्रम का प्रतीक माना जाता है।

रेवन्त का पराक्रम और देवताओं की चिंता : पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रेवन्त और अश्विनी कुमारों की दिव्य शक्तियां अत्यंत प्रभावशाली थीं। उनके तेज और सामर्थ्य से तीनों लोकों में उनकी विशेष प्रतिष्ठा होने लगी। उनकी असाधारण शक्ति को देखकर देवताओं के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्हें आशंका हुई कि यदि इस शक्ति का उचित नियमन नहीं हुआ, तो सृष्टि की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।समस्या के समाधान के लिए सभी देवता सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सृष्टि की मर्यादा और संतुलन बनाए रखने का उपाय पूछा। ब्रह्माजी ने देवताओं को भगवान शिव की शरण में जाने की



सलाह दी। इसके पश्चात सभी देवता कैलाशपति भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे सृष्टि के कल्याण की प्रार्थना की।भगवान शिव को देवताओं की चिंता का कारण ज्ञात हुआ। उन्होंने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। भगवान शिव का स्मरण होते ही दोनों दिव्य कुमार उनके समक्ष उपस्थित हो गए। महादेव ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपनी गोद में स्थान दिया और समझाया कि दिव्य शक्ति का वास्तविक उद्देश्य लोककल्याण, धर्म की रक्षा और सृष्टि की मर्यादा बनाए रखना है। सामर्थ्य तभी सार्थक होता है, जब उसका उपयोग जनकल्याण के लिए किया जाए।

**महाकाल वन में शिवलिं